आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 15.03.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं।
- सरकार ने पर्वतीय होली के दृष्टिगत राज्य में आज सार्वजनिक अवकाश घोषित किया।
- प्रदेश में उत्साह और उमंग का त्यौहार होली शांतिपूर्ण रूप से मनाया गया।
- केदारनाथ यात्रा में घोड़ा–खच्चरों की स्वास्थ्य निगरानी के लिए इस बार इंटरनल मॉनीटरिंग टैग–चिप लगाई जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन

उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 8 से 14 वर्ष तक के डेढ सौ बालक और डेढ सौ बालिका खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। चयन प्रदेश के हर जिले से छह अलग–अलग आयु वर्गों में किया जाएगा और चयनित खिलाड़ियों को पन्द्रह सौ रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वे खेल अभ्यास को सुचारू रूप से जारी रख सकें।

वहीं, 14 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ियों के लिए खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत दो हजार रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

खिलाड़ियों का चयन बैटरी टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की चयन प्रक्रिया 1 से 15 अप्रैल तक और खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना की चयन प्रक्रिया 16 से 30 अप्रैल तक चलेगी।

दोनों योजनाओं के लिए आवेदन 31 मार्च सायं 5 बजे तक खिलाड़ी www.khelouk.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अवकाश

पर्वतीय होली के दृष्टिगत राज्य सरकार ने आज प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव अनूप कुमार मिश्रा की ओर से जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार राज्य के अधीन समस्त शासकीय व अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, विद्यालयों में पर्वतीय होली के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यह अवकाश बैंकों, कोषागारों व उप कोषागारों पर लागू नहीं होगा।

होली

प्रदेश में कल पहाड़ से लेकर मैदान तक होली का पर्व बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। विभिन्न स्थानों पर तड़के से शुरू हुए होली के कार्यक्रम देर रात तक चलते रहे। साथ ही होलियारों ने घर–घर जाकर एक दूसरे को बधाई और शुभाकामनाएं दीं। होली के अवसर पर प्रदेशभर में जगह–जगह विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

कुमाऊं में बैठकी और खड़ी होली परम्परागत रूप से मनाई गई। होलियारों ने पारंपरिक ढोल–दमाऊं और मंजीरों की थाप पर जमकर होली के गीत गाए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार संग देहरादून स्थित राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ होली खेली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रंगोत्सव के त्यौहार से सभी को संकल्प लेकर उत्तराखंड को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना होगा। श्री धामी ने उधमसिंह नगर के खटीमा स्थित आवास में स्थानीय लोगों के साथ भी होली मनाई। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों को रंग लगाते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बैठकी होली में भी प्रतिभाग किया। वहीं, खेलमंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में परिवार और अन्य लोगों के साथ होली मनाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि होली समाज में समरसता का भाव पैदा करने वाला त्योहार है। रंगों का पर्व होली हमें विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को मानने वाले लोगों के बीच सौहार्द्र और शांति का संदेश देता है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि होली भाईचारे का त्यौहार है। वहीं होली में किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे इसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा।

फूल देई

होली के बीच लोकपर्व फूल देई भी पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया। पर्वतीय जिलों में बच्चों ने देहरी पूजन कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। चंपावत जिले में भी फूल देई मनाई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में बच्चों संग लोकपर्व फूलदेई का उत्सव मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति का आभार प्रकट करने और बसंत ऋतु के स्वागत का प्रतीक लोकपर्व फूलदेई न केवल सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, बल्कि हमारे प्राचीन रीति–रिवाजों को सम्मान देने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस विशेष अवसर पर स्थानीय वेशभूशा में सजे–संवरे बच्चों ने पारंपरिक गीतों के साथ वातावरण को उल्लासपूर्ण बना दिया।

इंटरनल टैग

आगामी दो मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा में इस बार घोड़ा–खच्चरों में इंटरनल मॉनीटरिंग टैग–चिप लगाई जाएगी। इसे लगाने से जानवरों की निगरानी होगी और उनके स्वास्थ्य के साथ ही पशु स्वामी और उत्पीड़न का भी पता चल सकेगा। इसके लिए रूद्रप्रयाग जिले में पशुपालन विभाग जल्द ही पशु चिकित्सा शिविर आयोजित कर घोड़ा–खच्चरों का पंजीकरण शुरू करेगा। वहीं इस बार के यात्राकाल के दौरान शासन व जिला स्तर चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई है। साथ ही संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी को यात्रा का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

गौरतलब है कि पहले चरण में चार से पांच हजार घोड़ा–खच्चरों का पंजीकरण किये जाने का लक्ष्य है। इससे पहले उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर अन्य जरूरी कार्यवाही पूरी की जाएगी।

घोड़े–खच्चरों के गले की त्वचा की पहली सतह पर इंजेक्शन के माध्यम से एक चिप लगाई जाएगी। इसके अलावा, पशुपालन विभाग द्वारा सोनप्रयाग और गौरीकुंड में घोड़ा–खच्चरों की जांच व इलाज के लिए अस्थायी अस्पताल संचालित भी किए जाएंगे। साथ ही पैदल मार्ग पर भी चिह्नित स्थानों पर इनके उपचार के लिए अस्थायी चिकित्सालय सीापित कर यहां रोस्टर के हिसाब से पशु चिकित्सक और अन्य कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। इस संबंध में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि किसी भी स्तर पर जानवर के उत्पीड़न के किसी भी स्थिति पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रकृति संरक्षण

और अब बात करते हैं बागेश्वर जिले के किशन मलड़ा की, जिन्होंने अपना जीवन प्रकृति को समर्पित कर दिया है। किशन पिछले 41 सालों से सूख रहे नौलों, धारों को पुनर्जीवत करने के साथ ही पौधारोपण में जुटे हैं। प्रकृति के प्रति उनके समर्पण के चलते उन्हें हर कोई अब वृक्ष पुरूष के नाम से जानता है। वृक्षप्रेमी किशन ने सूखती धाराओं में पानी बढ़ाने के लिए उसके आसपास चौड़ी पत्ती की प्रजाति के सैकड़ों पौंधे लगाए। पौंधे बड़े हुए तो इसका असर दिखने लगा और सूख चुकी जलधाराओं से पानी फिर से बहने लगा। श्री मलड़ा अभी तक करीब दस लाख से ज्यादा पौंधे लगा चुके हैं।

प्रकृति के प्रति प्रेम के चलते किसन मलड़ा को उत्तराखंड राज्य विज्ञान एंव प्रौद्यौगिकी परिषद, स्पर्श गंगा बोर्ड समेत दर्जनों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2018 में राज्यपाल ने उन्हें वृक्ष पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया। किशन मलड़ा का कहना है कि नदी, नालों और जल स्रोतों से पानी की कमी की मुख्य वजह पेड़, पौंधों की कमी है। चौड़ी पत्ती वाले पौधे जैसे उतीस, बांज, तिमिल, खरसूं, रिंगाल के वन विकसित करने से जल संकट की समस्या का समाधान किया जा सकता है।

जलसंस्थान

रूद्रप्रयाग जिले में जलसंस्थान ने तीन करोड़ रूपये की वसूली की। जिलाधिकारी के निर्देश पर जलसंस्थान से जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले में सघन वसूली अभियान चलाकर ये कार्रवाई की। अब भी सरकारी विभागों पर 80 लाख और निजी उभोक्ताओं पर एक करोड़ अस्सी लाख रुपये का बकाया है। जलसंस्थान द्वारा नियमित जलापूर्ति के तहत प्रत्येक माह मानकों के तहत बिल भेजा जाता है, जिसके तहत उपभोक्ता को निर्धारित धनराशि जमा करनी होती है, पर जिले में ऐसा नहीं हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में जलसंस्थान का सरकारी विभागों और निजी उपभोक्ताओं पर 5 करोड़ 60 लाख रुपये का बकाया था। जलसंस्थान के अधिशासी अभियंता अनीश पिल्लई ने बताया कि 31 मार्च तक बकाया राशि जमा करने वाले सरकारी विभागों व निजी उपभोक्ताओं से विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। अभी तक जिले में 35 से अधिक संयोजन भी काटे जा रहे हैं। साथ ही 60 अवैध संयोजन को पूरी प्रक्रिया के तहत वैध किया गया है। गौरतलब है कि जिले में जलसंस्थान की 294 पेयजल योजनाएं संचालित हो रही हैं। इन योजनाओं से जिला मुख्यालय सहित पांच निकाय और 600 से अधिक और गांवों में लाखों लोगों जल उपलब्ध कराया जा रहा है।